FORESTS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) According to the air quality survey, the air pollution levels in Delhi are by and large within the prescribed standards. While the levels of sulphur dioxide and oxides of nitrogen are well within the limits, the particulate matter is on the higher side. This is due to the natural dusty conditions and industrial activities including thermal power plants.

(b) The main factor responsible for air pollution in Delhi are industries and motor vehicles.

(c) The steps taken to check the pollution in Delhi include the following:—

(i) Ambient air quality standards have been prescribed.

(ii) Entire Union Territory of Delhi has been declared as air pollution control area.

(iii) Emission standards have been notified under the Environment (Protection) Act, 1986.

(iv) Industries have been directed to instal necessary air pollution control equipment on a time bound basis and to comply with the emission standards.

(v) The Indraprastha Thermal Power Plant is meeting the emission standards. Of the 2 new units at Rajghat, both have appropriate electrostatic precipitators. Of the 5 units at Badarpur Thermal Power Plant, Units 1, 4 and 5 have adequate electrostatic precipitators and are meeting the emission standards. Installation/retrofitting of electrostatic precipitators in the remaining 2 units is under completion.

(vi) Gross and mass emission standards for petrol as well as diesel-driven vehicles have been notified under the Motor Vehicles Rules, 1989. The gross emission standards notified under Rule 115(2) of the Motor Vehicles Rules have come into force with effect from 1.3.1990.

(vii) The Directorate of Transport, Delhi Administration has launched an education and awareness drive which consists of advertising campaign, checking of vehicles and issuing of warning slips to the vehicles which do not conform to the prescribed standards.

(viii) The Delhi Administration has initiated action on Government vehicles and buses of the DTC to ensure that they meet the standards notified.

निर्धनता निवारण

1829. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1990 के "दी हिन्दू" में मोर "फण्ड्स टू फाइट पावर्टी सज्जैस्टिड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विश्व बैंक की एक अध्ययन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या है और क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की व्यापक रूपरेखा तैयार करते समय सरकार ने इन आंकड़ों को ध्यान में रखा है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) संबंधित विश्व बैंक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वास्तविक आय का आंकलन करने तथा "गरीबी की रेखा" का निर्धारण करने की विभिन्न पद्धतियों से अलग-अलग निष्कर्ष निकलते हैं ; और यह कि उन्होंने कुछ परिभाषाएं अपनायी हुई हैं जिनसे गरीबी के मोटे अनुमान प्राप्त होते हैं ।

उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1970 के दशक तथा 1980 के दशक के प्रारम्भ से मध्य तक के दौरान, गरीबी को व्यापकता में गिरावट आई है और दक्षिण भारत में गरीबी के आपात में तेजी से गिरावट आई जिससे अब 3/5 से अधिक गरीब पूर्वी तथा मध्यवर्ती राज्यों में हैं ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण बनाया जा रहा है । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें चक्र के अनंतिम निष्कर्षों पर आधारित तथा जिस कार्यप्रणाली का प्रयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय किया गया था उसी का प्रयोग करते हुए वर्ष 1987-88 में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन पालन करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या का 29.2 प्रतिशत है ।

इलाहाबाद में गंगा जल का प्रदूषण

1830. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद में गंगा जल कितना प्रदूषित हो गया है ;

(ख) क्या यह जल स्नान करने के योग्य नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस जल को प्रदूषण-मुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री साथ में कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्नान के लिए निर्धारित की गई जल गुणवत्ता सूचकांक सीमा के सन्दर्भ में इलाहाबाद में वर्ष 1984 से 1989 तक जल गुणवत्ता में सुधार की प्रवृत्ति पाई गई है । डी0ओ0 और पी0एच0, ये दो पैरामीटर स्नान-योग्य जल के लिए स्वीकार्य सीमा तक लगातार मिलते रहे है और बी0ओ0डी0 में भी सुधार की प्रवृत्ति पाई गई हैं । तथापि, स्नान योग्य जल की सीमा से कॉलिफॉर्म की संख्या अधिक रही है । गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद में हाथ ; ली जाने वाली स्कीमों के पूरा हो जाने पर जल गुणवत्ता में और अधिक सुधार होने की संभावना है ।

(ग) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत, 21.65 करोड़ रुपये की वर्तमान संशोधित लागत पर 18 स्कीमें इलाहाबाद नगर के लिए अनुमोदित की गई हैं । इनमें से 10 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं और अन्य स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं । इलाहाबाद में हाथ में ली गई स्कीमों में नगर महापालिका अपशिष्ट जल के अवगोधन एवं दिशा-परिवर्तन की स्कीमें सीवेज उपचार संयंत्र, अल्प-लागत स्वच्छता निर्माण-कार्य, विद्युत शवदाह गृह तथा नदी तटाग्र सुविधाएं शामिल हैं ।

Supply of Irradiated food

†1830-A. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up a food Irradiation Unit in Cochin;

(b) if so, whether Government are aware that Australian Government is considering to ban irradiated food and that Japan has already banned its imports;

(c) whether it is also a fact that there is no method to test the irradiated food and that there is no scientific unanimity on such food being free from radio activity; and

(d) if so, what measures are contemplated by Government to ensure that irradiated food rejected by other countries is not dumped into the country by offering heavy discounts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY WITH ADDITIONAL

†Previously Unstarred Question 1484 transferred from the 26th March, 1990.